



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 3 दिसम्बर, 2003/17 अग्रहायण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

चम्बा-176 310, 1 नवम्बर, 2003

क्रमांक-पंच-चम्बा-52/98-1393-1403.—चूँकि खण्ड विकास अधिकारी मेहला की जांच रिपोर्ट संख्या 2450, दिनांक 16-9-2003 द्वारा रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि श्री ध्यान सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत कपाहड़ा, विकास खण्ड मेहला मास अप्रैल 2003 से जून, 2003 तक लगातार ग्राम पंचायतों की बैठकों में अनुपस्थित रहा है जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं०	मास	बैठकों की संख्या	बैठकों में अनुपस्थिति
1.	7-4-2003	1	अनुपस्थित
2.	24-4-2003	1	-उक्त-
3.	7-5-2003	1	-उक्त-
4.	24-5-2003	1	-उक्त-
5.	7-6-2003	1	-उक्त-
6.	24-6-2003	1	-उक्त-
योग ..		6	

अतः आपको लिखा जाता है कि आप उपरोक्त अनुपस्थिति दिनांकों के बारे में अपना उत्तर 15 दिनों के भीतर-भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) उप-धारा 2 कार्यवाही आरम्भ कर दी जाएगी।

राहुल आनन्द,
उपायुक्त चम्बा।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, KINNAUR DISTRICT AT R/PEO, H.P.

OFFICE ORDER

R/Peo, the 6th November, 2003

No. KNR-734/90-10756-61.—Whereas Shri Gopal Singh s/o Shri Sarkoo Ram, r/o Bara Kamba, Tehsil Nichar, District Kinnaur was elected as Member Panchayat Samiti, Nichar from Ward No. 2 Chhota Kamba during the general election of Panchayat Raj institutions in December, 2000.

And whereas it was come to the notice of the undersigned that Shri Gopal Singh has got 3rd child on 28-10-2002 after his election as Member Panchayat Samiti, Nichar.

And whereas inquiry was conducted through field agencies and it was found that Shri Gopal Singh has got 3rd child on 28-10-2002 after his election and entries of getting 3rd child has been made in the Parivar register of the concerned Gram Panchayat.

And whereas Shri Gopal Singh has been given ample opportunity to explain his position but he neither given the written reply nor appeared before me on 7-11-2003 to explain his position. Hence, it is clear that Shri Gopal Singh has contravened the provisions of Section 122 (1) (0) of Himachal Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2000.

Therefore, in exercise of the powers vested in me vide section 122 (2) (ii) of the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1994, I, Maneesh Garg, I.A.S., Deputy Commissioner, Kinnaur hereby disqualify Shri Gopal Singh s/o Shri Sarkoo Ram, R/o village Bara Kamba, Tehsil Nichar, District Kinnaur for holding the post of Member Panchayat Samiti, Nichar with immediate effect. Any record, articles or money of Panchayat Samiti, Nichar be taken back from Shri Gopal Singh immediately.

MANEESH GARG I.A.S.,
Deputy Commissioner, Kinnaur District at R/peo.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

मण्डी, 5 नवम्बर, 2003

संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-6414-20.—ग्राम पंचायत तुगांधार, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी (हि० प्र०) के अवधि 4/97 से 3/2002 तक के अंकेक्षण पत्र में उद्धृत गम्भीर अंकेक्षण आपत्तियों पर आधारित कारण बताओ नोटिस श्रीमती जस्सी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत, तुगांधार को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-5096-5101, दिनांक 3-9-2002 के अर्न्तगत जारी किया गया था। आरोपित उक्त पंचायत पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण

15 दिन के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। प्रधान ग्राम पंचायत से दिनांक 13-9-2002 को प्राप्त उत्तर व ग्राम पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर निम्न आधार पर स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुये निर्धारित आरोपों की पुष्टि की गई :-

1. यह कि प्रधान ग्राम पंचायत ने दिनांक 4-12-1998 को हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक जंजैहली से मु० 25,600/- (पचीस हजार छः सौ) रुपये बैंक संख्या 1483765 द्वारा निकाले गये हैं, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत की बचत खाता पास बुक से होती है, परन्तु उक्त बैंक के अध-पन्ना पर मु० 5000/- (पांच हजार) रुपये लिखे गये हैं तथा रोकड़ के पृष्ठ 12 पर भी मु० 5000/- रुपये की निकासी दर्शाई गई है। इस प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत मु० 20600/- रुपये का छलहरण किया गया है।

आरोप के सन्दर्भ में प्रधान ग्राम पंचायत का यह स्पष्टीकरण कि मु० 20600/- रुपये उन्होंने बैंक से निकाले तथा बाउचर काटकर पंचायत सचिव को दिये थे, स्वीकार्य नहीं है। अपने स्पष्टीकरण में उन काटे गये बाउचर का कोई उल्लेख नहीं है कि यह कितनी राशि के थे तथा किस निर्माण कार्य से सम्बन्धित थे। स्पष्टीकरण के साथ मस्ट्रोल संख्या : 482 मु० 27540/- रुपये अवधि 1-10-1998 से 31-10-1998 संलग्न है। मस्ट्रोल खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी किया बताया गया है, परन्तु मस्ट्रोल जारी करने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर मस्ट्रोल पर अंकित नहीं है। मस्ट्रोल पर निर्माण कार्य के नाम पर स्याही गिरी है, जिस कारण निर्माण कार्य जिसके लिये मस्ट्रोल जारी किया गया है, स्पष्ट नहीं है। मस्ट्रोल के अनुसार निर्माण कार्य का कौन सा कार्य करवाया गया स्पष्ट नहीं है, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड सराज से प्राप्त सूचना के अनुसार मस्ट्रोल 482 मास 10/98 ग्राम पंचायत छतरी का जारी किया गया है। विकास खण्ड सराज कार्यालय में संघारित अभिलेख के अनुसार मस्ट्रोल संख्या 478 से 490 तक मास 10/98 को ग्राम पंचायत छतरी को जारी किये गये हैं तथा मास मई, 1998 से मार्च, 1999 तक कोई भी मस्ट्रोल ग्राम पंचायत तुगांधार को जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त मस्ट्रोल की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है। प्रधान ग्राम पंचायत के इस कथन की सत्यता भी संदिग्ध है कि तीन वर्ष पूर्व उन्होंने यह मस्ट्रोल सचिव पंचायत को दे दिये थे। प्रधान ग्राम पंचायत का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपने द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि/पंचायत राशि का समायोजन सम्बन्धित निर्माण कार्यों की व्यय रसीदों की रोकड़ में नियमानुसार प्रविष्टि करवाकर करें। रोकड़ में की गई प्रत्येक प्रविष्टि प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापित की जाती है तथा पंचायत द्वारा किया गया प्रत्येक व्यय ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत कराना प्रधान ग्राम पंचायत का दायित्व है। विशेषकर जबकि व्यय प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं किया गया हो, परन्तु प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में अपने दायित्वों को किंचित भी वहन नहीं किया गया है।

2. यह कि प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा मु० 20600/- रुपये का छलहरण के फलस्वरूप पंचायत को व्याज से प्राप्त होने वाली आय की हानी हुई है और वाणिज्य दर से मु० 13596/- रुपये बनती है। यह राशि प्रधान ग्राम पंचायत से बसूली योग्य है।

3. यह कि दिनांक 4-12-1998 को मु० 25,600/- रुपये बैंक से निकासी की गई, परन्तु इस राशि को बैंक से निकालने की स्वीकृति बारे ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। बिना पंचायत की अनुमति से बैंक से राशि की निकासी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 99 (4) के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है, यह एक गम्भीर अनियमितता का मामला है। ग्राम पंचायत के बैंक खाते से राशि की निकासी ग्राम पंचायत के विधिवत प्रस्ताव पारित किये बिना अथवा फर्जी प्रस्ताव लिखकर बैंक से उपरवर्णित राशि की निकासी की गई है, जो कि धोखाधड़ी का एक अपराधिक मामला बनता है।

उपरोक्त आरोप के सम्बन्ध में पंचायत अभिलेख की जांच करने से पुष्टि हो गई कि मु० 25,600/- रुपये की जो बैंक से निकासी की गई इसकी अनुमति पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 5-11-1998 के अन्तर्गत जिसके द्वारा मु० 25,600/-

रूपये की निकासी ग्राम पंचायत के बचत खाता से की गई दर्शाई गई है। मूलतः खण्ड विकास अधिकारी को प्राथमिक पाठशाला भेखली के निर्माण हेतु मु० 20,000/- रुपये दूसरी किस्त के रूप में जारी करने की मांग करते हुये प्रेषित की है, ताकि उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री क्रय की जा सके। परन्तु इसी क्रम संख्या व दिनांक से हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक जंजैहली को प्रस्तुत प्रस्ताव में व मूल प्रस्ताव में इसके पारित हो चुकने के पश्चात अनियमित रूप से परिवर्तन/काट छांट कर उपरोक्त राशि हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक जंजैहली से निकाल ली गई है, जिसके लिए प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत की बैठक में प्रत्येक प्रस्ताव प्रधान ग्राम पंचायत की अनुमति से विचारार्थ रखा जाता है तथा कार्यवाही रजिस्टर में अंकित किया जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत के पारित प्रस्तावों के प्रमाणिक स्वरूप कार्यवाही के अन्त में प्रधान ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर अंकित होते हैं। प्रधान ग्राम पंचायत को इसका पूर्ण ज्ञान था कि मु० 25,600/- रुपये की राशि की बैंक से निकासी से सम्बन्ध कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में पारित नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने फर्जी प्रस्ताव हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक जंजैहली में प्रस्तुत कर उपर्युक्त राशि की निकासी कर दुर्विनियोजन को ही सिद्ध किया है।

4. ग्राम पंचायत के अभिलेख की जांच के निष्कर्ष के आधार पर जिसकी पुष्टि हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक जंजैहली से प्राप्त सूचना से भी हो गई है प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की अवधि 1-1-1997 से 1-10-2001 तक हि० प्र० राज्य सहकारी बैंक जंजैहली में ग्राम पंचायत तुगांधार की ओर से फर्जी/झूठे पंचायत प्रस्ताव जो विधिवत रूप से ग्राम पंचायत की बैठक में न तो पारित हुये, न ही इनका उल्लेख ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में है, तैयार किये व बैंक में विधिवत पारित प्रस्ताव के रूप में कपट पूर्वक प्रस्तुत कर मु० 9,57,453/- (नौ लाख सत्तान्न हजार चार सौ तरेपन्न) रुपये की छल ढंग से निकासी की है। प्रधान ग्राम पंचायत की उपरोक्त अनियमित कार्यवाही न केवल हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम व इनके अधीन बनाये गये नियमों की गम्भीर उल्लंघना है, अपितु एक अपराधिक मामला बनता है।

5. यह कि रोकड़ पृष्ठ 77 पर दिनांक 16-7-1997 को दर्ज प्रमाणक संख्या व मस्ट्रोल मास मई, 1997 में मजदूर क्रमांक 15 श्री नेत्र सिंह को 3-5-1997 से काम पर उपस्थित दर्शाया गया है तथा मजदूर क्रमांक 16 व 17 को 1-5-1997 से उपस्थिति दर्शाकर मु० 1317.60 रुपये का छलहरण किया है। मस्ट्रोल के अनुसार मजदूरी की अदायगी प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। मस्ट्रोल को प्रधान द्वारा स्थापित किया गया है। अतः उपरोक्त दर्शाई अनियमित अदायगी का उत्तरदायित्व प्रधान ग्राम पंचायत का है। इसी प्रकार रोकड़ पृष्ठ 36 पर दिनांक 20-1-2000 को निर्माण कार्य प्राथमिक पाठशाला भेखली के मस्ट्रोल तं० 186 वाउचर संख्या : 93 मास दिसम्बर, 1999 के मजदूर क्रमांक को 15 को दिनांक 4-12-1999 को उपस्थित बताया गया तथा मजदूर संख्या : 16 से 20 को 2-12-1999 से उपस्थित दर्शाया गया। इस प्रकार मु० 357/- रुपये का अधिक भुगतान करके सभा निधि राशि का दुरुपयोग व छलहरण हुआ है। जिसके लिए पदासीन प्रधान पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। क्योंकि उनके द्वारा मस्ट्रोल पर दर्शाये गये कार्य पर लगे व्यक्तियों की मजदूरी की अदायगी की है तथा मस्ट्रोल को प्रमाणित करते हुये हस्ताक्षर किये हैं।

आरोप के सम्बन्ध में प्रधान ग्राम पंचायत प्रस्तुत स्पष्टीकरण अस्पष्ट तथा आरोप के संदर्भ में नहीं है। अतः अस्वीकार्य है।

अतः मैं, श्री रजा रिजवी (भा० प्र० से०) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०) उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 में निहित है, श्रीमती जस्सी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत तुगांधार, विकास खण्ड सराज, जिला मण्डी (हि० प्र०) को तत्काल प्रधान पद से जनहित में निलम्बित

करता हूं और उन्हें निर्देश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत का कोई अभिलेख, धन तथा चल या अचल सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के पास सौंप दें।

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त, मण्डी,
जिला मण्डी (हि० प्र०)।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (ना०)
उप-मण्डल गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

अधिसूचना

मण्डी, 24 नवम्बर, 2003

संख्या 5866-5881.—ग्राम पंचायत मौवीसेरी, बस्सी में वार्ड पंचों के रिक्त पदों हेतु दिनांक 30-11-2003 को होने वाले उप-चुनावों के संचालन हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 32 (4) के प्रावधानों के अनुसार निम्न भवनों को उक्त चुनावों हेतु मतदान केन्द्र के रूप में अधिकृत किया जाता है :—

क्र० सं०	ग्राम पंचायत का नाम	भवन जिसमें मतदान केन्द्र स्थापित किया गया	निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	मतदाताओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मौवीसेरी	रा० मा० पा० मौवीसेरी	वार्ड नं० सेरी-I	202
2.	बस्सी	रा० प्रा० पा० बस्सी	वार्ड-2 टिकर-II	136

हस्ताक्षरित/-
प्राधिकृत अधिकारी
एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना०),
गोहर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या : पी०सी०एच०-एस०एम०एल० (4) 68/77-17106-12.—यह कि प्रधान/पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू की रिपोर्ट अनुसार श्री अम्बा दत्त, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक लगातार पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं इस तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग से करवाई गई। पंचायत की कार्रवाई पुस्तिका को छानबीन से पाया

गया कि उक्त श्री अम्बा दत्त, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरु उपरोक्त वर्णित दिनांकों को पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जिस कारण वह पंचायत सदस्य पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि इस बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अम्बा दत्त, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरु, विकास खण्ड ठियोग को कारण बताओ नोटिस संख्या : पी 0सी 0एच 0एस 0एम 0एल 0 (4) 68/77-4442-45, दिनांक 7-10-2003 को इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था जिसमें 15 दिन के भीतर-भीतर पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहने हेतु कारण स्पष्ट करने का समय दिया था। श्री अम्बा दत्त से कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है क्योंकि वह दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 28-12-2002 तथा 8-1-2003 तक निरन्तर पंचायत बैठकों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उसकी पंचायत के कार्यों में कोई रूची नहीं रह गई है, जबकि उसे इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2-9-2003 के अन्तर्गत नियमित रूप से बैठकों में भाग लेने हेतु परामर्श किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी वह ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि श्री अम्बा दत्त ने हि 0 प्र 0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) की उल्लंघना की है तथा वह ग्राम पंचायत धार-कन्दरु के सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

अतः मैं, एस 0 के 0 बी 0 एस 0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि 0 प्र 0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अधीन प्राप्त है, श्री अम्बा दत्त, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरु, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर, यह आदेश देता हूँ कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी/पंचायत सहायक ग्राम पंचायत धार-कन्दरु को सौंप दें।

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पी सी एच-एस एम एल (4) 68/77-17099-105.—यह कि प्रधान/पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार कन्दरु की रिपोर्ट अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत धार-कन्दरु, दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक लगातार पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं इस तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग से करवाई गई। पंचायत की कार्रवाई पुस्तिका की छानबीन से पाया गया कि उक्त श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत, धार-कन्दरु उपरोक्त वर्णित दिनांकों को पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जिस कारण वह पंचायत सदस्य पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि इस बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरु, विकास खण्ड ठियोग को कारण बताओ नोटिस संख्या पी सी एच-एस एम एल (4) 68/77-4442-45, दिनांक 7-10-2003 को इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। जिसमें 15 दिन के भीतर-भीतर पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहने हेतु कारण स्पष्ट करने का समय दिया था। श्री सुरेन्द्र सिंह से कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है क्योंकि वह दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक निरन्तर पंचायत बैठकों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट है कि उसकी पंचायत के कार्यों में कोई रूची नहीं रह गई है। जबकि उसे इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2-9-2003 के अन्तर्गत नियमित रूप से बैठकों में भाग लेने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु इसके बावजूद भी वह ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह ने हि 0 प्र 0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) की उल्लंघना की है तथा वह ग्राम पंचायत धार कन्दरु के सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं।

अतः मैं, एस 0 के 0 बी 0 एस 0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि 0 प्र 0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अधीन प्राप्त हैं, श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत धार कन्दरु, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर, यह आदेश देता हूँ कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो, उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी/पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार कन्दरु को सौंप दें।

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पी सी एच-एस एम एल (4) 68/77-17092-98.—यह कि प्रधान, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार कन्दरू की रिपोर्ट अनुसार श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक लगातार पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं इस तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग से करवाई गई। पंचायत की कार्रवाई पुस्तिका की छानबीन से पाया गया कि उक्त श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत, धार-कन्दरू उपरोक्त वर्णित दिनांकों को पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जिस कारण वह उप-प्रधान पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि इस बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग को कारण बताओ नोटिस संख्या पी सी एच-एस एम एल (4) 68/77-4442-45, दिनांक 7-10-2003 को इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 15 दिन के भीतर-भीतर पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहने हेतु कारण स्पष्ट करने का समय दिया था। श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान से कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है क्योंकि वह दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक निरन्तर पंचायत बैठकों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उसकी पंचायत के कार्यों में कोई रुचि नहीं रह गई है, जबकि उसे इस कार्यालय के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2-9-2003 के अन्तर्गत नियमिति रूप से बैठकों में भाग लेने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु इसके बावजूद भी वह ग्राम पंचायतों की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) की उल्लंघना की है तथा वह ग्राम पंचायत धार-कन्दरू के उप-प्रधान पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अधीन प्राप्त है, श्री नरेश कुमार, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धार कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर, यह आदेश देता हूँ कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो वह उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी/पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू को सौंप दें।

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पी0सी0एच0एस0एम0एल0(4) 68/77-17113-19.—यह कि प्रधान/सहायक ग्राम पंचायत, धार-कन्दरू की रिपोर्ट अनुसार श्री चन्दू लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू, दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक लगातार पंचायत की मासिक बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं इस तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, ठियोग से करवाई गई। पंचायत की कार्रवाई पुस्तिका की छानबीन से पाया गया कि उक्त श्री चन्दू लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू उपरोक्त वर्णित दिनांकों को पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जिस कारण वह पंचायत सदस्य पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि इस बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री चन्दू लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत धार-कन्दरू, विकास खण्ड ठियोग को कारण बताओ नोटिस संख्या पी0सी0एच0एस0एम0एल0(4) 68/77-4442-45, दिनांक 7-10-2003 को इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था जिसमें 15 दिनों के भीतर-भीतर पंचायत बैठकों से अनुपस्थित

रहने हेतु कारण स्पष्ट करने का समय दिया था। श्री चन्दू लाल से कारण बताओ नोटिस का जो उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया है क्योंकि वह दिनांक 26-11-2002 से 9-12-2002, 26-12-2002 तथा 8-1-2003 तक निरन्तर पंचायत बैठकों से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उनकी पंचायत के कार्यों में कोई रुचि नहीं रह गई है, जबकि उसे इस कार्यालय के समसंख्यांक ज्ञापन दिनांक 2-9-2003 के अन्तर्गत नियमित रूप से बैठकों में भाग लेने हेतु परामर्श दिया गया था परन्तु इसके बावजूद भी वह ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री चन्दू लाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (ख) की उल्लंघना की है तथा वह ग्राम पंचायत धार-कन्दरू के सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं।

अतः मैं, एस0के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) के अधीन प्राप्त है, श्री चन्दू लाल को सदस्य ग्राम पंचायत धार-कन्दरू, विकास खण्ड ठिथोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के सदस्य पद को रिक्त घोषित कर, यह आदेश देता हूँ कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो वह उसे तुरन्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी/पंचायत सहायक ग्राम पंचायत, धार-कन्दरू को सौंप दें।

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पी0सी0एच0एस0एम0एल0-(10) 145/82-17137-42.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी रामपुर, जिला शिमला ने पत्र संख्या आर0 बी0 (पंच)/3440, दिनांक 5 अगस्त, 2003, जो जिला पंचायत अधिकारी शिमला को सम्बोधित है के अन्तर्गत सूचित किया है कि श्री गोपी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली, उप तहसील ननखड़ी, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला ने अनाधिकृत रूप से मु0 76,402.00 रुपये की राशि अपने पास रखी है, जो कि एक गम्भीर मामला है और निधि का दुरुपयोग भी है:—

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर ने उक्त श्री गोपी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला को उक्त राशि की वसूली बारे नोटिस क्रमांक आर0 बी0 (पंच)/3213, दिनांक 10-7-2003 को दिया था परन्तु आज दिन तक उक्त प्रधान द्वारा यह राशि न तो पंचायत खाता में जमा करवाई गई तथा न ही नकद शेष वापिस लौटाई गई, जैसा कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली ने सूचित किया है अनाधिकृत रूप से रखी गई मु0 76,402.00 रुपये का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

1. अनुदान राशि नकद शेष के रूप में	65,902.00
2. 2001-2002 का पशु चिकित्सालय से प्राप्त किराया राशि	6,000.00
3. गृह कर व राशन कार्ड से वसूली राशि	4,500.00

कुल योग . . . 76,402.00

यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री गोपी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली को अनाधिकृत रूप में रखी गई मु0 76,402.00 रुपये की राशि को जमा पंचायत खाता करने तथा वसूली हेतु एक सप्ताह का समय देने के फलस्वरूप भी उक्त प्रधान द्वारा कोई कार्यवाही न की गई, जिससे न केवल विकास कार्य प्रभावित हुआ है बल्कि

पंचायत की राशि का दुरुपयोग भी हुआ है। उक्त राशि को प्रधान द्वारा अपने पास रख कर सभा निधि की हानि भी हुई है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि श्री गोपी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली, उप-तहसील ननखड़ी, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला अपने कार्य व कर्तव्यों को हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत भली भांति निभाने में विफल रहे हैं और अनाधिकृत रूप से अपने पास राशि रख कर प्रधान जैसे पद की गरिमा को ठेस पहुंची है, जिस कारण उक्त प्रधान को प्रधान पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(2) पठित हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोपी चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत, टिप्पर मझोली, उप-तहसील ननखड़ी, जिला शिमला, हि० प्र० को तत्काल प्रधान पद से निलम्बित करता हूँ तथा उन्हें यह आदेश देता हूँ कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत की कोई राशि अथवा सम्पत्ति रखी है तो उसे ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी टिप्पर मझोली को तुरन्त सौंप दें।

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पीसीएच-एसएमएल-6/2002-17133-36.—एतद्वारा श्री रमेश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेड़ी, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि० प्र०) का ध्यान हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्नतः है:—

कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निर्वाह्य होगा, “यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है”।

स्पष्टिकरण:—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद “सेवा” या “नियोजन” के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, आकस्मिक, दैनिक या संविदा पर नियुक्त, रखे गए या नियोजित व्यक्ति हैं।

यह कि सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, शिमला से उनके पत्र संख्या 6432/93-सह-शिकायत-3361 दिनांक 30-9-2003 द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार श्री रमेश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेड़ी के प्रधान पद पर रहते हुए दी धनेश्वर सहकारी उपभोक्ता समिति भरेड़ी में भी बतौर सचिव व विक्रेता के पद पर भी दिनांक 24-12-2002 तक कार्य करते रहे हैं जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-1 (छ) के अन्तर्गत वह इस पद पर रहते हुए प्रधान पद का चुनाव नहीं लड़ सकता था यदि उसे प्रधान पद का चुनाव लड़ना था तो उसे दी धनेश्वर सहकारी उपभोक्ता समिति भरेड़ी से सचिव व विक्रेता पद से नामांकन पत्र भरने से पूर्व अपना त्याग-पत्र देना चाहिए था। जिस कारण उक्त श्री रमेश चन्द, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (छ) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत भरेड़ी में प्रधान पद पर बने रहने के लिए निर्वाह्य पाए गये हैं।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री रमेश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भरेड़ी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि० प्र०) को उन्हें अपने

पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करता हूँ कि वे इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना उत्तर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार एकतरफा कार्यवाही प्रमल में लाकर ग्राम पंचायत भरेड़ी का प्रधान पद रिक्त घोषित कर दिया जायेगा।

एस0के0बी0एस0 नेगी,
उपायुक्त शिमला,
जिला शिमला (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 27 नवम्बर, 2003

संख्या पी0सी0एच0-एस0एम0एल0 (त्यागपत्र) 8/2003-17127-32.—यह कि श्रीमती कला देवी सदस्या, ग्राम पंचायत लोयरकोटी, विकास खण्ड रोहड़ू, जिला शिमला की नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 1-5-2003 को हुई है जिस कारण उन्होंने ग्राम पंचायत लोयरकोटी के सदस्य पद से त्याग-पत्र दिया है। खण्ड विकास अधिकारी रोहड़ू ने पत्र संख्या रो0बी0पंच/2003-1877, दिनांक 20-11-2003 के अन्तर्गत श्रीमती कला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत लोयरकोटी के त्यागपत्र स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कला देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत लोयरकोटी के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूँ तथा सदस्य पद वाई नं0 2, ग्राम पंचायत लोयरकोटी को रिक्त घोषित करता हूँ।

हस्ताक्षरित/-
जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 25 नवम्बर, 2003

सं0-पी0सी0एच0-एस0एम0आर0-11203-209.—यह कि उप-मण्डल अधिकारी (ना0), राजगढ़ को श्रीमती प्रसन्नी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत दीदग, विकास खण्ड राजगढ़ के विरुद्ध शिकायत सौंपी गई, जांच रिपोर्ट तथा खण्ड विकास अधिकारी, राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत कुछ विकास कार्यों में प्रधान द्वारा राशि के दुरुपयोग बारे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त प्रधान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आसोपों के विवरण सहित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर आरोपवार श्रीमती प्रसन्नी देवी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :—

आरोप संख्या-1.—दिनांक 24-4-2002 की ग्राम पंचायत दीदग की बैठक की कार्यवाही पर कार्यवाही रजिस्टर में अपनी मोहर व हस्ताक्षर काटे जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया कि उस

अपने हस्ताक्षर कार्यवाही रजिस्टर से इसलिए काटे थे क्योंकि यह बैठक उसकी अध्यक्षता में होते हुए भी सारी कार्यवाही सहायक सचिव के माध्यम से उप-प्रधान द्वारा लिखवाई गई थी। किन्तु प्रधान द्वारा प्रस्तुत यह तर्क तर्कसंगत नहीं है।

आरोप सं०-2.—निर्माण पक्की गली खनोटियों पर रोकड़ वही के पृ० सं० 49, दिनांक 29-4-2002 तथा पृ० सं० 56, दिनांक 12-10-2002 के अनुसार दर्शाये गये कुल व्यय मु० 19,405/- रुपये तथा तकनीकी मूल्यांकन मु० 17,600/- रुपये के आरोप बारे प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया है।

आरोप सं०-3.—निर्माण बाबड़ी खनोटियों पर रोकड़ वही के पृ० सं० 51, दिनांक 16-7-2002 के अनुसार दर्शाये गये कुल व्यय मु० 11,700 रुपये तथा तकनीकी मूल्यांकन मु० 4,100 रुपये के आरोप बारे भी प्रधान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः मैं, एम० एल० शर्मा, भा० प्र० से०, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती प्रसन्नी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत दीदग, विकास खण्ड राजगढ़ को प्रधान पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूँ ताकि उसके इस पद पर बने रहने से ग्राम पंचायत दीदग के रिकार्ड से वह छेड़छाड़ अथवा कांट छांट न कर सके तथा साक्ष्य मिटाने का या साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास न कर सके। उक्त श्रीमती प्रसन्नी देवी को ग्राम पंचायत दीदग की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से वर्जित किया जाता है। यदि उनके पास ग्राम पंचायत दीदग का कोई भी रिकार्ड हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंपा जाना सुनिश्चित किया जाये।

एम० एल० शर्मा,

उपायुक्त,

जिला सिरमौर, नाहन (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 21 नवम्बर, 2003

संख्या सोलन-3-92 (पंच)/III-7029-35.—खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर ने अपने पत्र संख्या डी० बी० डी० (पंच) 2909, दिनांक 31-10-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया जाता है कि उनके खण्ड में ग्राम पंचायत बढलग, वार्ड नं० 5 के सदस्य श्री श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय ईश्वर दास ने अपनी नौकरी एक लिमिटेड कम्पनी में लगने के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दिया है।

अतः मैं, सम्पूर सिंह आजाद, जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बढलग, वार्ड नं० 5, के त्याग-पत्र को स्वीकार करते हुए पंच पद को रिक्त घोषित करता हूँ।

आदेश द्वारा,

सम्पूर सिंह आजाद,

जिला पंचायत अधिकारी,

सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

